www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 16 जनवरी 2019

दैनिक जागरण

गुस्से में कभी कुछ न करें, क्योंकि तब हर चीज गलत होगी

अस्थिरता की राजनीति

इस पर आश्चर्य नहीं कि कर्नाटक एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता से घिरता दिख रहा है। इसका अंदेशा तभी उभर आया था जब विधानसभा चुनाव बाद सीटों के मामले में तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल-एस ने दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। हालांकि पहले नंबर पर आई और साधारण बहुमत से दूर रही भाजपा ने भी जोड़-तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। वास्तव में जब जनादेश निर्णायक न हो तो ऐसा ही होता है। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को या तो जोड़-तोड़ करनी पड़ती है या फिर परस्पर विरोधी दलों को एक साथ आना पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में जनादेश का निरादर होता है। जैसा कर्नाटक में हुआ वैसा ही कई अन्य राज्यों में भी हो चुका है। सच तो यह है कि केंद्र में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। बावजूद इसके इस सवाल का जवाब खोजने की कहीं कोई कोशिश नहीं हो रही है कि त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में साफ-सुथरे तरीके से सरकार का गठन कैसे किया जाए ताकि राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति मिलने के साथ ही आयाराम-गयाराम की राजनीति को पनपने का अवसर न मिले। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि निर्णायक जनादेश के अभाव में सरकार गठन का कोई तर्कसंगत उपाय इसीलिए नहीं खोजा जा रहा ताकि जोड़-तोड़ से सरकार बनाने के अवसर बने रहें। इसका दुष्परिणाम केवल यह नहीं है कि सरकारें राजनीतिक अस्थिरता से घिरी रहती हैं और वे विकास एवं सुशासन पर बुरा असर डालती हैं, बल्कि यह भी है कि राजनीतिक मौकापरस्ती और सौदेबाजी को बल मिलता है। आमतौर पर यह सौदेबाजी भ्रष्टाचार और कुशासन को फलने-फूलने का ही मौका देती है। शायद राजनीतिक दलों को इसमें ही अपना हित दिखता है।

कर्नाटक की मौजूदा सरकार कांग्रेस के साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है। शायद ही किसी मतदाता ने ऐसी सरकार की आकांक्षा की हो या फिर इस हेतु वोट दिया हो। अभी तक तो जद-एस और कांग्रेस में खटपट की ही खबरें आ रही थीं, लेकिन अब दो निर्दलीय विधायकों के इस सरकार से अलग होने की भी खबर है। एक खबर यह भी है कि कर्नाटक के भाजपा विधायकों ने गुरुग्राम में डेरा जमा लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की मानें तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं और वहां के भाजपा नेताओं पर यकीन करें तो वे चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गुरुग्राम आए हैं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि सच कुछ और ही हो सकता है। अगर कर्नाटक में नए सिरे से राजनीतिक समीकरण बनते-बिगड़ते हैं और उसके फलस्वरूप वहां नई सरकार बनती है तो इससे जोड़-तोड़ की राजनीति को ही बल मिलेगा। इस नई सरकार को भी राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इस सबसे अगर कोई घाटे में रहेगा तो वह होगी कर्नाटक की जनता। यदि राजनीतिक दलों को जनता के हितों की तनिक भी परवाह है तो उन्हें गठबंधन राजनीति के कायदे-कानून बनाने और त्रिशंकु जनादेश की हालत में एक सक्षम सरकार बनाने के तौर-तरीके तय करने के लिए आगे आना चाहिए।

नक्सलवाद पर वार

नक्सल समस्या राज्य की एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये राज्य के विकास में बाधक है। नक्सली नहीं चाहते कि विकास हो, क्योंकि इससे उनकी गतिविधियों पर असर पड़ता है। लेकिन सरकार भी तत्पर है कि नक्सलियों के इरादों को नेस्तनाबूत कर दिया जाए और जन-जन तक विकास पहुंचाया जाए। इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। हाल ही में दुमका में हार्ड कोर ताला दा का मारा जाना इसी कड़ी का हिस्सा माना जाना चाहिए। ताला दा संताल परगना में आतंक का पर्याय था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में लीड भूमिका अदा की थी। उस पर 50 से अधिक मामले दर्ज थे। माओवादियों के गढ़ पारसनाथ में 100 से अधिक नक्सली पकड़े जा चुके हैं। आज स्थिति ये है कि वहां नक्सलियों को कैडर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि पारसनाथ जोन से निकले एक-एक करोड़ के इनामी तीन माओवादी मिसिर बेसरा, प्रशांत बोस और प्रयाग माझी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। प्रशांत बोस भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो का एवं अन्य दोनों सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। सुरक्षा बल अब इनकी तलाश में लगे हैं। ये पकड़े गए तो तय है कि नक्सलियों की रीढ़ ही टूट जाएगी। नक्सलवाद की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वे सिद्धांत से विमुख हो चुके हैं। निजी हित, लेवी वसूली इनका मुख्य ध्येय हो गया है। बार-बार यह सामने आता है कि फलां नक्सली का बेटा बड़ी जगह पढ़ रहा है। लेवी के पैसे से ही उसकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि संगठन की बेरुखी के कारण कई नक्सलियों का मोहभंग हो रहा है, क्योंकि केस-मुकदमा हो जाए तो संगठन उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। इन परिस्थितियों के मद्देनजर माना जा सकता है कि अगर दबाव और बढ़ाया जाए तो नतीजा सकारात्मक रहेगा। संगठन से ऊब चुके नक्सलियों के लिए बेहतर जीवन के अवसर पैदा किए जाएं जिससे उन्हें भी लगे कि संगठन छोड़ने के बाद वो मुख्यधारा में आ सकेंगे, सर उठाकर जी सकेंगे।

तालिबान का दुस्साहस बढ़ाता अमेरिका

विवेक काटजू

अमेरिका इसकी अनदेखी कर रहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने के लिहाज से कोई ठोस कदम इसलिए नहीं उठा रहा, क्योंकि वह वहां भारत को नियंत्रित करना चाहता है

इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी और भूमिका में कटौती करना चाहते हैं। यह विदेश नीति में उनकी एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह काफी अधीर हो रहे हैं। इस मकसद के लिए अमेरिका ने पिछले वर्ष अक्टूबर में जालमी खलीलजाद को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त कर उन्हें तालिबान से वार्ता करने की जिम्मेदारी भी सौंपी ताकि तालिबान हिंसा छोड़कर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी और मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला के साथ संवाद शुरू करे। तीन दौर की वार्ता के बावजूद खलीलजाद अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए राजी नहीं कर पाए हैं। 9 जनवरी को कतर में जो वार्ता होनी थी वह भी तालिबान के रवैये के कारण स्थगित हो गई। तालिबान अमेरिका के साथ धींगामुश्ती में लगा है और अपने उसी अड़ियल रुख पर कायम है कि अमेरिका सहित अन्य सभी फौजें अफगानिस्तान से चली जाएं। वह अफगानिस्तान सरकार को भी अमेरिका की कठपुतली मानता है। अपनी अनर्गल टिप्पणियों से ट्रंप खलीलजाद की राह और मुश्किल बना रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने अफगानिस्तान में भारतीय मदद एवं सहयोग को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि भारत वहां पुस्तकालय बना रहा है, लेकिन क्या वहां कोई पढ़ता भी है? उन्होंने यह भी कहा कि भारत वहां जो मदद कर रहा है, अमेरिका वहां उतना पांच घंटे में खर्च कर देता है। तालिबान से लड़ने में कुछ देशों के सैन्य सहयोग पर भी ट्रंप ने अपमानजनक बातें कहीं। उनके ऐसे बयानों पर भारतीय बौद्धिक वर्ग के एक तबके में नाराजगी स्वाभाविक ही है। यह अच्छा रहा कि नई दिल्ली और काबुल ने भारत की मदद के स्वरूप से जुड़े तथ्यों को सामने रखा। भारतीय मदद को अफगान जनता की स्वीकार्यता भी मिली हुई है, यह उन्हीं क्षेत्रों में हो रही है जिनमें अफगान सरकार उससे अपेक्षा करती है।

मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने अमेरिकी जनरलों की भूमिका को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने उलाहना देते हुए कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में अच्छे नतीजे नहीं दिए हैं और इसी कारण यह लड़ाई 19 साल लंबी खिंच गई। ट्रंप का यह मानना स्वाभाविक है कि अपने इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई में अमेरिकी सैन्य बल नाकाम रहे हैं, लेकिन इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस नाकामी में अमेरिकी नेताओं की वह हिचक भी जिम्मेदार है जिसके चलते पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाने की अनिच्छा दिखाई गई। ट्रंप के बयान की यही व्याख्या की जाएगी कि तालिबान के खिलाफ बढ़त बनाने में उन्हें अमेरिकी सैन्य बलों पर भरोसा नहीं। ऐसी लाचारी से केवल तालिबान का दुस्साहस ही बढ़ेगा और वह अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा रह सकता है। ट्रंप के रुख-रवैये से अफगानिस्तान सरकार के साथ वहां की जनता का मनोबल भी कमजोर होगा। मीडिया के समक्ष ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जहां अफगानिस्तान से छह हजार मील दूर है और फिर भी वह वहां संघर्ष में जुटा है वहीं भारत, पाकिस्तान और रूस जैसे देश जिनके अफगानिस्तान से क्षेत्रीय हित सीधे जुड़े हुए हैं, इस लड़ाई से दूर हैं। वह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका के धन और बल पर बोझ को इन देशों द्वारा भी साझा किया जाना चाहिए। इसमें कुछ देशों का उन्होंने जिक्र किया तो कुछ का नहीं किया। यह उनके भीतर की कारोबारी प्रवृत्ति का ही परिचायक है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनकी कारोबारी पृष्ठभूमि है। इसी कारण अपने 12 पूर्ववर्तियों के उलट अन्य देशों के वित्तीय योगदान को लेकर उनका रवैया ज्यादा स्पष्ट और मुखर है, लेकिन अमेरिका इससे बेपरवाह दिखता है कि अफगानी जनता रूसी या पाकिस्तानी फौज को अपनी जमीन पर कभी नहीं उतरने देगी, क्योंकि वह उन्हें अपनी अधिकांश समस्याओं का जिम्मेदार मानती है। भारत भी स्पष्ट कर चुका है कि वह अफगानिस्तान में अपने सैनिक नहीं भेजेगा, पर भारत-अफगान सामरिक साझेदारी समझौते को देखते हुए सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण देने के साथ ही अफगान सुरक्षा बलों को मेडिकल सहायता देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत की यह मंशा ट्रंप के कारण नहीं, बल्कि इस वजह से है कि नई दिल्ली को अपना हित इसी में दिखता है।

अवधेश राजपूत

अफगानिस्तान में भारत के योगदान पर ट्रंप के बयान के बाद उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बात हुई। बातचीत के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई। इस बातचीत के तुरंत बाद खलीलजाद ने भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि तीन महीनों से खलीलजाद भारत आने से कतरा रहे थे जबकि उन्होंने अफगानिस्तान के लिहाज से कई अहम देशों के दौरे किए। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि भारत का दौरा कर वह पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहते थे जिसकी अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका है। तमाम सकारात्मक बयानों के बावजूद पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने के लिहाज से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, क्योंकि वह अफगानिस्तान की भारत नीति को नियंत्रित करना चाहता है। अभी तक किसी भी अफगान सरकार ने उसे यह छूट देने के संकेत भी नहीं दिए हैं। भारी अस्थिरता के दौर से जूझ रहे अफगानिस्तान में जहां गनी-अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान समर्थित नई ताकत और मनोबल से लैस तालिबान से मोर्चा ले रही है तो भारत को उसे हरसंभव मदद मुहैया करानी चाहिए। अफगानिस्तान सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी के दो पूर्व प्रमुखों अमरुल्ला सालेह और असदुल्ला खालिद को आंतरिक और रक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा है। इन दोनों काबिल और अनुभवी अफसरों की कैबिनेट में मौजूदगी से अफगान लोगों के साथ ही तालिबान और पाकिस्तान के साथ मसलों के सुलझने की उम्मीद बंधी है। अफगानिस्तान को तमाम मोर्चों पर मदद के साथ ही भारत को तालिबान के साथ वार्ता का विकल्प भी खुला रखना चाहिए, क्योंकि सभी बड़े देश ऐसा कर रहे हैं।

इसी के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भारत न तो तालिबान को पसंद करता है और न ही उसकी विचारधारा को। अंतराष्ट्रीय कूटनीति ऐसे ही काम करती है। इसके तहत कई ऐसे समूहों से भी बात करनी पड़ती है जो आपकी आंखों में खटकते हों। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विदेश मंत्री ही इस मामले में कोई पक्ष रखें, न कि सेना प्रमुख। कूटनीति की कमान विदेश मंत्री के हाथ में होती है, सेना प्रमुख के काम का दायरा दूसरा है। दोनों को अपनी भूमिकाओं को लेकर दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल गफलत ही पैदा होगी।

(विदेश मंत्रालय में सचिव रहे लेखक अफगानिस्तान मामलों के विशेषज्ञ हैं)

response@jagran.com

मनचाहा नतीजा निकालने की आजादी

राजीव सचान

सीबीआइ प्रकरण इसका भी उदाहरण है कि आज किसी को मसीहा बनाना या बदनाम करना कितना आसान है

तथ्यों की मनमानी व्याख्या कर किसी संदिग्ध आचरण वाले व्यक्ति को किस तरह मसीहा बनाने की कोशिश हो सकती है और किसी असंदिग्ध आचरण वाले व्यक्ति को संदिग्ध करार दिया जा सकता है, इसका सटीक उदाहरण हैं सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एके सीकरी। जिन्होंने यह मान और ठान लिया था कि आलोक वर्मा एक ईमानदार और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले सीबीआइ निदेशक थे वे उनकी ऐसी छवि पर आंच न आने देने के लिए इस कदर आमादा हुए कि उन्होंने जस्टिस सीकरी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जस्टिस सीकरी उस उच्च स्तरीय चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल थे जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा के भविष्य का फैसला करना था। इस तीन सदस्यी समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता के तौर पर कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। खड़गे की मांग थी कि आलोक वर्मा को न केवल पूरे अधिकार दिए जाएं, बल्कि उनके कार्यकाल में वे 77 दिन भी जोड़ दिए जाएं जो उनकी छुट्टी में खप गए थे। उनसे ऐसे ही किसी रवैये की अपेक्षा थी। उनकी कोई अपेक्षा इसलिए पूरी नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जस्टिस सीकरी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मौजूदा हालात में आलोक वर्मा को स्थानांतरित करना ही बेहतर होगा। हालांकि इस निष्कर्ष पर पंहुचने के आसार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ही निहित थे जिसके तहत आलोक वर्मा की बहाली तो की गई थी, लेकिन उन पर नीतिगत फैसला न लेने की बंदिश भी लगाई गई थी। इसका यही मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पाक-साफ नहीं पाया था।

आलोक वर्मा के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच की निगरानी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पटनायक भले ही यह कह रहे हों कि वर्मा को जल्दबाजी में स्थानांतरित किया गया और उन्हें अपनी सफाई का अवसर नहीं दिया गया, लेकिन यह तथ्यों के विपरीत है। कम से कम उन्हें यह पता होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने का पूरा मौका दिया था। उन्होंने सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दिया भी था, जिसके मीडिया तक पहुंच जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था। एक सच यह भी है कि खुद जस्टिस पटनायक ने आलोक वर्मा को क्लीनचिट देने के बजाय यही कहा था कि कुछ आरोपों की आगे जांच की जरूरत है। इस सवाल का जवाब जस्टिस पटनायक ही दे सकते हैं कि अगर उनकी नजर में आलोक वर्मा पाक-साफ थे तो फिर वह इस नतीजे पर पहुंचे ही क्यों कि उन पर लगे कुछ आरोप गंभीर किस्म के हैं और उनकी जांच होनी चाहिए? सवाल यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर में आलोक वर्मा बेदाग थे तो उसने उन्हें क्लीनचिट देने के बजाय उनकी बहाली बंदिशों के साथ क्यों की? एक सवाल यह भी है कि इन बंदिशों के बावजूद आलोक वर्मा दोबारा कामकाज संभालते ही अपनी अनुपस्थिति में किए गए फैसलों को पलटने में क्यों जुट गए थे? यह तय है कि ये सारे सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते जो यह मान चुके हैं कि आलोक वर्मा तो भ्रष्ट तत्वों के लिए काल बन चुके थे और मोईन कुरैशी जैसे लोग उनके नाम से ही कांप उठते थे। आने वाले दिनों में इस आशय की खबरें भी दिखने लगें तो हैरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने जस्टिस एके सीकरी की छवि को तार-तार किया।

जस्टिस सीकरी का गुनाह मात्र यह था कि मुख्य न्यायधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर यह जानते हुए भी भेजा कि वह मार्च में रिटायर होने के बाद कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सदस्य बन जाएंगे। चूंकि मोदी सरकार ने इस ट्रिब्यूनल के सदस्य के तौर पर सीकरी को मुख्य न्यायाधीश की सहमति मिलने के बाद ही नामित किया था इसलिए ऐसा कुछ मान लेने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि शायद इसके बारे में वह अवगत नहीं रहे हों। बावजूद इसके आलोक वर्मा के स्थानांतरण के फैसले के बाद जस्टिस सीकरी के बारे में यह प्रचारित किया गया कि सरकार की कृपा से कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सदस्यता हासिल करने के एवज में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय प्रधानमंत्री की राय का समर्थन किया। जस्टिस सीकरी को कठघरे में खड़ा करने के लिए यह भी रेखांकित किया गया कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सदस्य एक मलाईदार पद है। जबकि तथ्य यह है कि ऐसे सदस्य को न तो कोई नियमित वेतन मिलता है और न ही लंदन में रहने की सुविधा। जस्टिस सीकरी को सरकार की कृपा से उपकृत दिखाने के क्रम में इसकी भी अनदेखी करने में ही भलाई समझी गई कि जब उन्होंने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सदस्य बनने को लेकर अपनी सहमति दी थी तब आलोक वर्मा के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ था। जो यह साबित करना चाह रहे कि जस्टिस सीकरी सरकार की कृपा से उपकृत हो गए वे इसकी भी अनदेखी कर रहे कि उच्च स्तरीय चयन समिति में अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें भेजने का फैसला खुद मुख्य न्यायाधीश गोगोई का था। जिन्हें लगता है कि जस्टिस सीकरी ने चयन समिति की बैठक शुरू होते ही आनन-फानन प्रधानमंत्री के मत का समर्थन कर दिया वे इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि फैसले के एक दिन पहले भी एक बैठक हुई थी। ऐसा नहीं है कि जस्टिस सीकरी कोई ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिन्होंने सरकार की पहल पर सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार करने को तैयार हुए हों, लेकिन उनके खिलाफ अभियान इसलिए छिड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का समर्थन कर दिया।

हालांकि आलोक वर्मा के स्थानांतरण के बाद जस्टिस सीकरी को लांछित करने के अभियान का प्रतिवाद भी किया गया, पर जब उनके साथ काम कर चुके सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज ने ऐसा किया तो उनसे पूछा गया कि वह किसकी दलाली खा रहे हैं? हालांकि जस्टिस सीकरी ओर से कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सदस्य बनने को लेकर दी गई अपनी सहमति वापस लेने के साथ ही इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होता दिख रहा है, लेकिन यह प्रसंग इस बात को साबित करता है कि आज के दौर में किसी को बदनाम करना अथवा मसीहा बनाना कितना आसान हो गया है। यह इसीलिए हो गया है, क्योंकि अब तथ्यों को ताक पर रखकर मनमाना नतीजा निकालने की प्रवृत्ति से राजनीति के साथ ही मीडिया का एक हिस्सा भी ग्रस्त हो गया है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चुनौतियों की सुंदरता

चुनौतियों से पार पाने के लिए जीवन में सहने का अभ्यास जरूरी है। इसके बिना किसी का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना होता है। यह एक सार्वभौम सत्य है। समस्याओं को देखने के लिए भी सकारात्मक नजरिया बहुत अपेक्षित होता है। क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार समस्याओं का रूपांतरण होता रहता है। जो सहिष्णुता, धैर्य एवं आत्मविश्वास का कवच धारण कर लेते हैं उनके लिए समस्याएं भी समाधान बन जाती हैं। आज जिन राष्ट्रों में सुख-सुविधा के साधनों का विस्तार हो रहा है, वहां सहने का अभ्यास घटता जा रहा है। परिणामस्वरूप वहां नाना प्रकार के मनोरोगों की वृद्धि हो रही है तथा आत्महत्या के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं।

खुद के बारे में सच जानना हो तो जरूरी है कि आप यह महसूस करें कि आप एक बेहतर इंसान हैं। जो लोग खुद को बुरा मानते हैं, वे आमतौर पर हारे और टूटे हुए होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अच्छाई आती कहां से है? दरअसल जीवन में ऊंचाई और गहराई का समन्वय आवश्यक है। हर व्यक्ति के मन में ऊंचाई पर पहुंचने का आकर्षण है, पर गहराई के बिना ऊंचाई भी वरदान नहीं होकर अभिशाप सिद्ध होती है। भारत की जीवनशैली में जो परिपक्वता, स्थिरता है, यह ऊंचाई और गहराई के समन्वय का परिणाम है। इसी के परिणामस्वरूप विश्व के प्रबुद्ध लोगों के मानस में यहां के मौलिक आदर्शों और संस्कारों के प्रति आदर का भाव रहा है। भारतीय दर्शन के अनुसार तरक्की की यात्रा अकेले नहीं हो सकती। जरूरी है कि आप अपने साथ दूसरों को भी आगे ले जाएं। उनके जीवन पर अच्छा असर डालें। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कितनी ही बार आपकी एक हंसी, एक हामी, छोटी सी मदद दूसरे का दिन अच्छा बना देती है।

किसी भी कार्य के प्रारंभ में अवरोधों का सामना करना होता है। जो उनसे विचलित हो जाते हैं वे अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। जो धीरज से आगे बढ़ते हैं वे उन अवरोधों का निराकरण खोजने में सफल हो जाते हैं। जिंदगी उन्हीं का साथ देती है, जो अपने बल पर कुछ अलग करने की ठानते हैं। जितने बड़े सपने होते हैं, जीवन उतना बड़ा नजर आता है।

ललित गर्ग

कुंभ में किन्नर अखाड़ा

रमेश ठाकुर

किन्नरों के मौजूदा कुंभ में प्रवेश से एक पुरानी रूढ़िवादी रिवायत खत्म हो गई है। किन्नर समाज के लिए यह नए युग के समान है

तारीखें बदलती हैं, रिवायतें बदलती हैं। साथ ही धराशाही हो जाती हैं रूढ़िवादी परंपराएं, लेकिन यह सब निर्भर उस पर करता जो इसका साक्षी बनता है। कुंभ मेला-2019 में भी एक सदियों पुरानी रूढ़िवादी रिवायत बदली गई है और उसके योद्धा बने हैं हमारे समाज के कुछ खास लोग। किन्नर समाज ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद नए युग का आगाज किया है। उनके इस कारनामे से 2019 से कुंभ मेले का सदियों पुराना इतिहास अब नए सिरे से लिखा जाएगा। किन्नरों ने अपने बूते छुआछूत से लबरेज एक पुरानी दीवार को गिराया है। कुंभ मेले में शामिल होने वाले अधिकृत अखाड़ों की घोर नाराजगी और मनाही के बाद भी प्रशासन ने इस बार किन्नर अखाड़े को भी कुंभ में शामिल होने दिया है।

कुंभ मेले में शामिल होने वाला किन्नर समाज का चौदाहवां अखाड़ा है। प्रयाग में मकर संक्रांति के पावन दिन से प्रथम शाही स्नान के साथ कुंभ मेले का आगाज हो गया है। पहले दिन देश-विदेश से आए करोड़ों भक्तों ने गंगा में डूबकी लगाकर उगते सूर्य को नमस्कार किया। आखिरी शाही स्नान चार मार्च होगा और इसी दिन कुंभ मेले का समापन भी हो जाएगा है।

पूर्व के कुंभ मेलों के मुकाबले इस बार ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए इंतजाम भी युद्धस्तर पर किए गए हैं। पहले ही दिन मेले में हजारों की संख्या में साधु-संतों का जुटान हुआ, जिनमें अधिकृत मान्यता प्राप्त तेरह अखाड़ों के संत शामिल हुए, इनमें सात शैव, तीन वैष्णव व तीन उदासीन (सिख) अखाड़े शामिल हैं। सबसे मजे की बात ये है कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो रहा है। इस लिहाज से इस बार तेरह नहीं, बल्कि चौदाह अखाड़े कुंभ में शामिल हुए हैं।

नए किन्नर अखाड़े को इस बार 14वें नए अखाड़े के तौर पर कुंभ प्रशासन ने मान्यता दी है। आधिकारिक रूप से मान्यता मिलने के बाद उनकी धूमधाम से पेशवाई निकाली गई। किन्नर अखाड़े में पच्चीस सौ किन्नर साधु शामिल हैं। अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी हैं। कुंभ में किन्नर अखाड़े को शामिल कराने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी भूमिका अदा की है। संतों के तमाम विरोध के बावजूद भी उन्होंने किन्नरों को कुंभ में आमंत्रित किया।

कुंभ में जितने भी अखाड़े भाग ले रहे हैं उनकी अपनी-अपनी विशेषता और महत्ता है। बाकायदा सबके अगल-अलग कानून होते हैं। किन्नरों ने भी अपने लिए प्रोटोकॉल बनाया है जिसे उनके सदस्य फॉलो करेंगे। सभी अखाड़ों की दिनचर्या और इष्टदेव अलग-अलग होते हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा (शैव) प्रयाग, ओंकारेश्वर, काशी, त्रयंबकेश्वर, कुरुक्षेत्र, उज्जैन और उदयपुर में है, जबकि इसका केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। इसका संबंध मुख्यतः उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म चढ़ाने वाले महंत निर्वाणी अखाड़ा से है। अटल अखाड़ा (शैव) के इष्टदेव भगवान श्रीगणेश कहे जाते हैं। इसका केंद्र काशी में है। इनके शस्त्र-भाले को सूर्य प्रकाश के नाम से जाना जाता है। किन्नर अखाड़ा ने अपने धर्म और सूत्र को मानवता के दूत की संज्ञा दी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

महापर्व कुंभ का आध्यात्मिक महत्व

निरंकार सिंह ने अपने आलेख 'सांस्कृतिक चेतना का महापर्व' में जिस तरह से कुंभ के आध्यात्मिक मेले को भारत की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाला बताया है, वह एक शाश्वत सत्य है। भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर आयोजित होने वाले कुंभ-पर्व आमजन की आध्यात्मिक आस्था को प्रगाढ़ करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में प्रवाहित होने वाली पुण्य प्रसूता भागीरथी के तट पर आयोजित होने वाले कुंभ का आकर्षण साधु-संत तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इस बार कुंभ स्थल के साथ ही संपूर्ण प्रयाग नगरी को जिस आध्यात्मिक रंग में रंगा गया है, वह अद्भुत है। अध्यात्म हमारे मन की नकारात्मकता को दूर कर, जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में धर्मजनित आध्यात्मिक आस्था को मनुष्य के कल्याण का कारक बताया गया है। दस मानवीय लक्षणों से युक्त धर्म को जीवन-पद्धति माना गया है। अब यह बात अलग है कि पाश्चात्य संस्कृति में रंगे हुए कुछ आधुनिकतावादी लोग इस देश के अध्यात्म और संस्कृति को ढकोसला मानकर इससे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अति भौतिकवाद से त्रस्त पश्चिम के लोग जब अपने मन की शांति के लिए भारतीय अध्यात्म की शरण में आते हैं तो सुखद आश्चर्य होता है। प्रयागराज कुंभ में करोड़ों विदेशियों का आना इस बात का प्रमाण है कि भारत के अध्यात्म ने पश्चिम के भौतिकवाद को जीत लिया है। कुंभ के माध्यम से भारत की इसी आध्यात्मिकता को उभारने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. विष्णु प्रकाश पाण्डेय, अलीगढ़

गठबंधन में गांठ!

उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के ताजा गठबंधन पर लगी

मेलबाक्स

गांठ के बाद रालोद और कांग्रेस में कुछ हताशा और निराशा स्वाभाविक है। इससे भाजपा को कुछ लाभ हो सकता है। यही हाल देश के अन्य प्रांतों में भी है, जिससे त्रिशंकु संसद की भी संभावना नजर आ रही है। इससे उत्पन्न खंडित जनादेश की स्थिति में तो चुनाव बाद ही कोई नया गठबंधन बन सकता है, जिसमें बड़ी पार्टी कांग्रेस से ही पीएम होना भी स्वभाविक है। इसमें राहुल गांधी की जगह अन्य कोई भी हो सकता है। अभी सपा नेता अखिलेश ने नए साल में नए पीएम की बात की है, मगर अब तो नए पीएम की जगह नए प्रोग्राम की कहीं अधिक जरूरत है। सभी के लिए सही रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण और पूरे देश के लिए जाम और प्रदूषण रहित अच्छे प्लान की ठोस व्यवस्था जरूरी है।

vedmamurpur@gmail.com

शर्मनाक है ऐसी घटनाएं

धरती पर जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, आज उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट की घटना चिंता जनक है। देश में कोई भी नियम से चलने को तैयार नहीं है। 70 बरस बीत जाने के बाद भी देश व्यवस्थित नहीं हो पाया। डॉक्टर्स के साथ मारपीट का यह कोई पहला मामला नहीं है। कभी शिक्षक को पीटा जाता है तो कभी पुलिस को जान से मार दिया जाता है। यह चिंता का विषय है। लोग पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबको यह समझना होगा और अपने समाज को बदलना होगा। यह तभी संभव हो सकता है, जब सब मिलकर इसके लिए आगे आएंगे।

ashishgusain234@gmail.com

गठबंधन, बहुगठबंधन और महागठबंधन!

नए साल की पहली तारीख को प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार के हवाले से जनता बनाम महागठबंधन जैसे राजनीतिक एजेंडे की झलक पेश कर दी। बहरहाल यह साल चुनाव वर्ष के नजरिये से भी खास है। ऐसे में सियासत के चौरस पर मोहरों की आजमाइश लाजिमी है। आगामी आम चुनावों में मुख्य मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ही होना तय माना जा रहा है। जबकि राष्ट्रीय दलों से इतर भारी-भरकम क्षेत्रीय क्षत्रपों से सुसज्जित राजनीतिक दलों में गठबंधन, बहुगठबंधन और महागठबंधन के संभव प्रयास तेज हो गए हैं। सियासी तोल-मोल की इन कोशिशों में लक्ष्य की बेदी पर नीतियों को बलि चढ़ना ही होगा। सत्ता के कुरुक्षेत्र में हार से सभी भयभीत दिखते हैं। जबकि हाल के प्रादेशिक चुनाव के नतीजों ने इस डर को और भी पुख्ता कर दिया है। तो फिर किसी भी पक्ष और दल के लिए गठबंधन का एक मजबूरी बन कर उभरना अप्रत्याशित नहीं कहा जाएगा। ऐसे में चुनौती न केवल विपक्षियों के लिए होगी, बल्कि जनता को भी खरा उतरना होगा।

mkmishralz@yahoo.in

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के तहत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।